(ख) से (घ) आवास राज्य का विषय है और राज्य सरकारें अपनी योजनागत प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य योजनागत निवेश में से सामाजिक आवास योजना चला रही है।

राष्ट्रीय आवास नीति में आवास विकास कार्यकलापों में प्राइवेट सैक्टर द्वारा निवेश हेतु निम्नलिखित योजनागत दिशा निर्देशों का उल्लेख किया गया है:—

(i) प्राइवेट विकास कर्ताओं और संगठित सैक्टर को धन मुहैया कराकर योजनाओं के शीघ्र अनुमोदन तथा अन्य प्रकार की सहायता, भूमि के संगठन और विकास में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके आवास और भूमि विकास के विभिन्न स्वरूपों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे निचले तथा मध्यम आय वर्गों के लिए सस्ती कीमतों पर मकान बनाने में महत्वपूर्ण निवेश करेंगे और शोषण रहित पद्धतियों का अनुपालन करने के लिए प्रेरित होंगे।

(ii) प्राइवेट सैक्टर तथा निजी व्यक्तियों द्वारा आवास कार्य क्षेत्र में वांछित निवेश का संवर्द्धन करने के लिए तथा परिवारों और उद्योगों से आवास कार्य के लिए अतिरिक्त बजट जुटाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

(iii) उद्योग सहित संगठित क्षेत्र के रोजगार दाताओं को अपने कामगारों को आवास मुहैया कराने के लिए प्रेरित करने हेतु विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों के लिए किराया अथवा स्वामित्व आवास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

तथापि, प्राइवेट सैक्टर को किस ढंग से और किस हद तक इस काम में जोड़ा जाएगा इसका निर्णय परिस्थितियों के आलोक में राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है।

Supply of Pure Drinking Water in Delhi

1857. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether with the growing flow of sewage from various areas of the city into Yamuna, Government have made any scientific analysis with regard to the quality of drinking water being supplied to the Delhi citizens;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what measures have been taken by Government to ensure supply of pure drinking water to the Delhi citizens?

THE MINISTER OF SATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) to (c) The Delhi Water Supply & Sewage Disposal Undertaking (DWS&SDU) has intimated that the 6 zonal laboratories situated at Wazirabad, Bhagirathi, Okhla, Haiderpur, Okhla Tank and Najafgarh overhead tank, fuly equipped with sophisticated equipments check and control the quality of drinking water right from raw water stage upto the consumer's end. Those laboratories are collecting about 250-300 water samples everyday from their respective zonal areas including rural areas to check the water quality for its potability and to ensure that no contamination of water takes place during transmission of water through Municipal mains. A mobile laboratory is also deployed to check the water quality in rural areas.

As a precautionary measure service reservoirs are cleaned periodically to maintain potability of water. Complaints received from public are attended promptly. Water quality from tubewells, deep bore hand pumps and ranney wells is also tested on regular basis. People are advised not to use shallow hand pump water for drinking purposes. All shallow hand pumps in resettlement colonies have been painted in red colour with indication not fit for drinking. As soon as complaint of contamination is received, water samples are immediately checked and in case of any abnormality, water supply to the area disconected and alternate supply is made through water tankers. The cause of contaminations investigated and rectified. Thereafter supply is restored after flushing the water lines.

Through Press Notifications, public at large is regularly advised to contact the above laboratories for free testing of water quality in case of any complaint.

Government Accommodation for Long Waiting Employees

1858. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have decided to bail out the out-of-turn allottees of Government accommodation, which the Supreme Court had ruled illegal allotment and ordered evictions;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government had taken into consideration the cases of Government employees who have not been allotted any accommodation despite rendering more than 25 years of service, before taking the above decision; and

(d) if so, the remedial steps taken to redress their grievances?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) The out of Turn Allotment of Residence (Validation) Ordinance, 1997 was promulgated on 21.6.97 to save out of turn allotees from eviction on humantarian grounds following the desire expressed by all the political parties. However, the out of turn allottees involved in subletting and who obtained such allotments by mis-representation of facts, by fraudulent means or where such allotment was of higher type than their entitlement, shall be evicted. A Bill has been introduced in the Lok Sabha to replace the Ordinance.

(c) and (d) A high powered Committee was set up under the Chairmanship of Director-General, Central Public Works Department, to consider the need for construction of more residential accommodation for augmenting the housing stock for General Pool. Two representations of the employees were associated with the Committee which has submitted its report.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फलैटों का बिना बारी आवंटन

1859. **श्री ईशदत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान बिना बारी के आवंटित किए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की आवंटितियों के नामों के साथ संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इसके मुख्यतः क्या कारण हैं;

(ख) ये आवंटन किन-किन क्षेत्रों में किए गए, भुगतान किस रूप में किया गया, किन-किन व्यक्तियों का आवंटन किया गया और ऐसे आवंटन किनकी सिफारिशों पर किये गए;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा विगत उक्त वर्षों के दौरान वर्षवार कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया था और उनमें से कितने फ्लैटों का आवंटन किया गया है; और

(घ) क्या न्यू पैटर्न हाउसिंग स्कीम, 1979 के आवंटितियो को मनोवांछित बस्ती चुनने का विकल्प नहीं दिया गया था?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सूचना के अनुसार गत पांच वर्षों के दौरान, 256 बिना-बारी आधार पर आवंटित किये गये थे। इन आबंटनों बाबत आवंटियों के नाम और आधार सहित आवंटन इलाके के वर्ष-वार ब्यौरे अनुपत्र में हैं। [देखिए परिशिष्ट 181 अनुपत्र संख्या 49] में हैं। बिना-बारी आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नकद भुगतान के आधार पर किये जाते हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत पांच वर्षों में निर्मित फ्लैटों का वर्ष विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	निर्मित फ्लैट
1992-93	7076
1993-94	0661
1994-95	6044
1995-96	2290
1996-97	7743

आबंटित फ्लैटों के वर्ष वार ब्यौरे नहीं दिये जा सकते, क्योंकि आबंटन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें वापस किये गये और निरस्त किये गये फ्लैट भी पुनः आबंटन हेतु शामिल होते है।